जन गर्जन

वर्ष 23 अंक 12 मासिक नई दिल्ली अगस्त 2009 विक्रमी संवत्-2066 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक-शुल्क: 60रुपये

भाजपा के लिये अखाड़ा बना जिन्ना की धर्मनिरपेक्षता

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

यह अजीब है कि भारत के विभाजन के 62 वर्षों के बाद भी हमारे देश के एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े नेताओं का एक वर्ग पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की धर्मनिरपेक्ष अवधारणा की भूमिका पर भ्रमित है। अगर हम देश की आजादी संघर्ष अभियान के परिप्रेक्ष्य में इतिहास में झांकेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि हमारी जनसंख्या के दो प्रमुख घटकों हिन्दु और मुसलमान के बीच देश को सांप्रदायिक टकराव का सामना करना पड़ा था। हिन्दु हमारी जनसंख्या का सबसे बड़ा घटक है। इसके बावजूद भी हमारे देश में कुछ मुस्लिम सहित अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हमारी जनसंख्या का लगभग 16 प्रतिशत है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों आदि की विविधता होने के बावजूद भी इनमें एकता और सौहार्द्ध हमारे देश की विशेषता है। भारतीय उपमहाद्वीप में साम्प्रदायिक सद्भाव, एकता और विश्वास की भावना युगों से युगों से चली आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य से, ब्रिटिश कब्जे से छुटकारा के बाद हमारे देश में अक्सर इस सांप्रदायिक सौहार्द्ध को कभी-कभी परेशान किया जाता है। यह ऐतिहासिक सत्य है कि साम्राज्यवादी ब्रिटिश ताकत ने भारत पर शासन करने के लिये हमें साम्प्रदायिक नुकसान पहुँचाकर 'फूट डालो और शासन करो' की नीति के आधार पर उसने हम पर दो सौ साल तक शासन किया। लेकिन दुर्भाग्य से, उस समय के विदेशी शासक हमेशा देशी एजेन्टों की खोज में रहते थे जो उनके फुट डालने की नीति में सहायता कर सके। भारतीय उपमहाद्वीप में मौहम्मद अली जिन्ना उस समय मुस्लिम सम्प्रदाय में बड़े और शक्तिशाली नेता थे, जो मुख्य धरती से हटकर मुस्लिम बहुल एक पृथक राज्य बनाने में सफल हो गये। ब्रिटिश शासकों की सक्रिय मदद से और समर्थन से तीन अलग राज्यों भारत, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बांग्लादेश) का निर्माण हो गया। जिन्ना के नेतृत्व में धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया और इस विभाजन में एक मुस्लिम देश उद्‌गम हुआ। यद्यपि भारत में 16 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या के बावजुद धर्मनिरपेक्ष देश बना रहा, जबकि पाकिस्तान की अवधारणा के पीछे मौहम्मद अली जिन्ना की पूर्व सुनियोजित सोच की एक खोज है। पाकिस्तान के उद्‌गम के साथ ही इसमें धर्मनिरपेक्षता का कोई स्थान नहीं था, अत: भाजपा के नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह की खोज के अनुसार जिन्ना जाहिर तौर को प्रख्यात और धर्मनिरपेक्ष का चैम्पियन नहीं हो सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना के दशकों पुरानी चली आ रही विभाजन की गतिविधियों को नजरअंदाज करके पाकिस्तान के संविधान सभा में मात्र एक बयान अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता।

अगर हम भारत में ब्रिटिश राज के उन उपद्रवी दिनों को याद करें तो, हमें महसूस होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम और लीग और अन्य किस प्रकार भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के लिये लड़े थे। जिन्ना ने अपने उस समय के स्लोगन 'इस्लाम खतरे में है' के कुख्यात साम्प्रदायिक भड़कावे के साथ अपने मिशन में कामयाब हो गया और पूरे देश में घृणा और हिंसा की स्थिति पैदा हो गयी, जिसके कारण 16 अगस्त 1946 से शुरू हुई खतरनाक कलकत्ता दंगा, जिसमें हजारों की संख्या में निर्दोष हिन्दू और मुस्लिम समुदाय के हजारों पुरुष एवं महिलायें दंगे में मारे गये, अत: सत्ता का हस्तांतरण के साथ अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हो गया। नेताजी कि गाथाओं और आजाद हिन्द फौज की जज्बातों से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को इसने पूरी तरह तोड़ दिया। छात्र और युवा आंदोलनों, नौसेना में विद्रोह, सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना आदि में साम्राज्यवाद विरोधी लहर नवम्बर 1945 से जुलाई 1946 तक अपने चरम पर पहुँच चुका था। लेकिन 1946 से 1947 के बीच का महत्वपूर्ण वर्ष सब कुछ सांप्रदायिक दंगे और सत्ता के हस्तांतरण के लिये सौदेबाजी की श्रृंखला के अंतर्गत खो गया था। जिन्ना की पाकिस्तान की महत्वकांक्षा परिपूर्ण हो चुकी थी और लेकिन सत्ता की प्राप्ति के लिये उस समय के कांग्रेसी नेता भी मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में साझेदारी के लिये गुप-चुप तरीके से हाथ मिलाने के लिये कम जिम्मेदार नहीं थे। विभाजन की इस दु:खद प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिये ब्रिटिश शासकों ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभायी।

इस तरह की स्थिति में, जिन्ना जैसे लोगों को एक महान धर्मनिरपेक्ष की संज्ञा देकर प्रस्तुत करना काफी कठिन है। लेकिन जसवंत सिंह ने हाल ही की अपनी पुस्तक 'जिन्ना - इण्डिया, पार्टिशन, इण्डिपेन्डेन्स' में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर, बहुत से विरोध उभरकर सामने

आये और अंततः जसवंत सिंह को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। यह वही पार्टी है जो स्वयं को विविधताओं की पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन यह कभी भी अपने अंतर्कलह से उभर नहीं पायी। 2005 में, पार्टी के मुखिया लाल कृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष कह कर बड़ी प्रशंसा की थी। अपनी इस टिप्पणी के लिये आलोचना का सामना करना पड़ा था और पार्टी नेतृत्व से हटाने की कोशिश की गयी थी। इस बार जसवंत सिंह पार्टी से निष्कासित कर दिये गये जिससे इस पार्टी के अन्दर की अंतरविरोधी संघर्षों पर प्रकाश डालती है। भाजपा की संसदीय बोर्ड जिन्ना के बारे में जसवंत सिंह के विचारों को एक वैचारिक भूल मानती है लेकिन किसी भी विचार पर उन सबकी असहिष्णुता इस मामले में उभरकर सामने आ रही है। आरएसएस के मजबूत समर्थन और दबाव के कारण, भाजपा के साथ-साथ विभिन्न नामों से चल रहे अन्य संगठनों कभी भी अपने सांप्रदायिक मुद्दों से आजाद नहीं हो सकते है। भारत की हिन्दु-मुस्लिम एकता सांप्रदायिक भाजपा के इस पखण्ड को अच्छी तरह जानती है और वह इनके भ्रम को मिटा देगी। आगे, भाजपा के कुछ बड़े नेताओं द्वारा जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में प्रस्तुत करने से पार्टी की छवि नहीं बदल सकती, बल्कि इससे सिर्फ पार्टी का अंतर्लकलह ही बढ़ेगा। साम्प्रदायिकता एक ऐसी धमकी है जिसने हमारी आजादी की लड़ाई को काफी नुकसान पहुँचाया है और अब यह हमारे शान्ति प्रयासों को ध्वस्त करने की कोशिश करता रहेगा। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसे महान महान दूरदर्शी ने अपने देशवासियों को चेतावनी दी थी की सांप्रदायिक भावनाओं से दूर रहो और धर्म, जाति और संप्रदाय विहीन एक मजबूत भारत बनाओ जो भारत की जन मानस की मजबूत एकता पर आधारित हो। समय आ गया है, की हमारे इतिहास को विकृत करने वालों और हमें भ्रमित करने वालों के प्रयासों को नकार देना चाहिये, जैसा कि भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा अब किया जा रहा है। सच्चाई का सामना करो और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सपनों का एक मजबूत समाजवादी भारत बनाओं।

एक बार विदाय दे माँ, घुरे आसिम

ए.आई.एस.बी. और ए.आई.वाई.एल. का शहीद खुदीराम बोस के 101 वीं शहादत दिवस पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन

मुजफ्फरपुर जेल : खुदीराम बोस का अंतिम गीत 'एक बार विदाय दे माँ, आमि घुरे आसि, हाँसि-हाँसि पड़बो फाँसी, देखबे भारतवासी', इस गीत से भारत माता से अंतिम विदाई लेने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस के क्रान्ति के जज्बे को सैकड़ों ए.आई.एस.बी. (ऑल इण्डिया स्टूडेन्ट्स ब्लॉक) के सदस्यों ने सलामी दी। मंगलवार दिनांक 11 अगस्त 2009 को उनके 101 वें शहादत दिवस पर पूरा केन्द्रीय कारागार श्रद्धानत हो उठा।

कारागार परिसर स्थित शहीद खुदीराम बोस सेल और फांसी स्थल को नमन करने के लिये 300 से भी अधिक लोग उमड़ पड़े। कई युवक तो सेल की दीवारों और फांसी स्थल के चबूतरे को स्पर्श कर ही रोमांचित हो रहे थे। शहीद खुदीराम बोस की राष्ट्रभक्ति की चेतना का महज आकलन कर कई लोगों की आंखें सजल हो उसी। खासकर पश्चिम बंगाल से आये ऑल इण्डिया स्टूडेन्ट्स ब्लॉक के 100 से अधिक छात्रों ने अपने इस प्रिय शहीद के फांसी स्थल को जीभर कर निहारते रहे। लोगों ने दोनों स्थानों पर शहीद खुदीराम बोस के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। खुदीराम बोस को दिये गये फांसी के समय पर ही सुबह 3.55 बजे आयोजित कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा देशभक्तों की श्रद्धांजलि से पूरा माहौल भावुक हो उठा। कार्यक्रम के लिये विशेष रूप से आये पश्चिम बंगाल के आपदा प्रबंधन व कृषि तथा बाजार मंत्री डॉ. मुर्तजा हुसैन ने सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। काराधीक्षक रूपक कुमार के अलावा जेल प्रशासन के अन्य अधिकारी भी व्यवस्था संचालन में पूरी तरह मुस्तैद रहे। कारागृह के अंदर श्रद्धांजलि देने के बाद लोगों ने कारागृह परिसर स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर भ्ज्ञी फूल माला चढ़ाकर उन्हें सलामी दी। श्रद्धांजलि के बाद ऑल इण्डिया स्टूडेंट्स ब्लॉक के महासचिव अमरेश कुमार सिंह ने समारोह में बिहार सरकार के किसी मंत्री के नहीं होने को दुःखद बताया और कहा कि यह आश्चर्य कि बात है कि देश के इस महान सपूत के लिये भी राजनीतिज्ञों के पास समय नहीं रहा। इसके अलावा अमरेश कुमार सिंह ने मांग की कि सेल और फांसी स्थल को सार्वजनिक किया जाना चाहिये। समारोह में कई राजनीतिक व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों की भी भागीदारी रही। पश्चिम बंगाल के मंत्री डॉ. मुर्तजा हुसैन ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि शहीद खुदीराम बोस के सेल और फांसी स्थल को स्मारक के रूप देकर उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिये। इससे लोग अपनी इच्छा से कभी भी आकर शहीद खुदीराम बोस को नमन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह स्थल देश की धरोहर है। इससे आम लोगों की संवेदना जुड़ी है। डॉ. हुसैन ने कहा कि इसके लिये वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगें।

इसके उपरान्त ऑल इण्डिया स्टूडेन्ट्स ब्लॉक एवं ऑल इण्डिया यूथ लीग ने जूरन छपरा स्थित अतुल कांन्फ्रेंस हाल में समारोह आायेजित कर शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी। जिले के अलावा पूर्णिया, पटना, पश्चिम बंगाल के सैकड़ों सदस्यों ने समारोह में शिरकत कर अपनी संवेदना निवेदित कि। समारोह की अध्यक्षता यूथ लीग के साथी अजय अग्निहोत्री ने की। ऑल इण्डिया यूथ लीग के महासचिव साथी संजय भट्टाचार्य ने कहा कि हमें एकबार पुनः मातृभूमि को खून भी देना होगा तो हम परहेज नहीं करेंगे। साथी अमरेश कुमार ने कहा कि आम आदमी आजादी से आज भी

कोसों दूर है। शिक्षा व स्वास्थ्य की पहुँत अभी तक सभी गांवों तक नहीं हो सकी है। अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा के जिला अध्यक्ष साथी राकेश कुमार सिंह ने पाठ्य पुस्तकों से क्रांतिकारियों की जीवनी का गायब होना चिंताजनक बताया। इस अवसर पर अम्ब्रीक महतो, यज्ञानंद मधुकर, फारवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक जयन्त सिंह व सुदीप बनर्जी ने भी अपने विचारों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

छात्रों–युवाओं का जुलूस : ऑल इण्डिया स्टूडेन्ट्स ब्लॉक एवं ऑल इण्डिया यूथ लीग ने 11 अगस्त 2009 को शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देने के विशाल जुलूस निकालकर राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। जूरन छपरा स्थित अतुल कान्फ्रेंस हाल से निकले इस जुलूस में सैकड़ों महिलाओं व पुरुष वंदे मातरम् का नारा लगाते हुये शहर के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। जुलूस में बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा पश्चिम बंगाल इकाई के युवा भी शामिल थे।

पर्यावरण की चुनौतियों को गंभीरता से लेना चाहिए

पर्यावरण सुरक्षा को लेकर उपस्थिति चुनौतियों से निपटने के लिए इस समय हमें सेमिनार आदि आयोजित करने के बजाय मिलकर एक समुचित और सकारात्मक कार्ययोजना तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। यह मुद्दा हमें सबसे ज्यादा चिंतित करता है क्योंकि सरकार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरणों को गंभीरता से लेने और उसे महत्व देने में हमेशा से बुरी तरह विफल साबित हुई है। इसके साथ ही इस दिशा में उसकी कार्य योजनाएं, सुझाव और संस्तुतियों का भी ठीक से परिपालन नहीं हो पा रहा है।

अक्सर यह देखा जा रहा है कि मंत्रालय और उनके विभाग अपनी परियोजनाओं को शुरू करने के पूर्व पर्यावरण प्राधिकरणों के सुझावों और उनकी आपत्तियों पर जरा भी ध्यान नहीं देते और उसे नजरंदाज करते रहते हैं। इस तरह खुद सरकार के ही पर्यावरण प्राधिकरणों की विश्वसनीयता संकट में आ गयी है। सरकारी विभागों द्वारा पर्यावरणीय आपत्तियों को नजरंदाज करने का सबसे घटिया उदाहरण और उच्चस्तरीय मिलीभगत हाल–फिलहाल निर्माण क्षेत्र में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए यमुना बेसिन में बन रहे खेलगांव के मामले में देखने को मिला है। इस विरोधाभासी मुद्दे का दूसरा पक्ष तो और भी बहुत गंभीर मसला है। इसमें पर्यावरणीय अनापत्ति लेने में घोर भ्रष्टाचार लंबे समय की एक आदत सी बन गयी है। इस तरह का भ्रष्टाचार और अनापत्ति लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल सी हो गयी हुई है कि एक नये तरह का लाईसेंस राज ही स्थापित हो गया है। हमें इस बात से खुशी है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देर से सही इस स्थिति की गंभीरता को समझा है और नई दिल्ली में 19 अगस्त को आयोजित राज्यों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों के सम्मेलन में पहली बार इस बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आम धारणा यह बन गयी है कि पर्यावरणीय अनापत्ति भ्रष्टाचार का बड़ा जरिया बन गया है और इससे निपटने की जरूरत है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस व्यवस्था को पूरी तरीके से स्वच्छ और पारदर्शी बनाने की जरूरत है।

वास्तव में इस जरूरत को लंबे समय से महसूस किया जा रहा है और हम इसकी लगातार मांग करते रहे हैं। अब जबकि खुद प्रधानमंत्री के मुंह से यही बात निकली है तो हम आशा करते हैं कि इस बारे में सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे और साथ ही पर्यावरण मामलों पर बने प्राधिकरणों को उचित महत्व और स्थान दिया जाएगा। पर्यावरणीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट अब न केवल मनुष्यों के लिए गंभीर चुनौती रह गये हैं बल्कि अब यह जानवरों और वनस्पतियों, यहां तक कि खुद पर्यावरण को भी अपने आगोश में लेने लगे हैं।

इसलिए अब जरूरी हो गया है कि इस गभीर मुद्दे पर पूरी सतर्कता और गंभीरता से ध्यान दिया जाए। दुर्भाग्य से, कुछ राजनीतिक दल, खासकर तृणमूल कांग्रेस इस समस्या की तात्कालिकता पर गौर करने में असफल रहे हैं। जब पंश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार ने घातक वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए गंभीरता से मानक तय करना शुरू किया और इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हाईकोर्ट के आदेश के तहत आदेश दिया कि 15 साल से अधिक समय के हो गये वाहनों को तुरंत सड़कों से हटा दिया जाना चाहिए, तो तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने राज्य में ऐसे गुनाहगार ऑपरेटरों और वाहन मालिकों की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से सरकार की इस नीति का न केवल विरोध किया बल्कि इन वाहन मालिकों को भी सरकारी आदेश न मानने के लिए उकसाना शुरू किया।

विपक्ष का यह कदम पूरी तरह से राजनीतिक विरोध है और राज्य की जनता के हितों के खिलाफ है। इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। खासकर ऐसे समय में जब, तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद केंद्र की संप्रग सरकार मे मंत्री हैं, उन्हें पर्यावरण सुरक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलानी चाहिए और उन्हें पर्यावरण विरोधी गतिविधियों को बंद करना चाहिए।

राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक सम्मेलन कोलकाता में सपन्न

8 अगस्त 2009 को कोलकाता में किदरीपुर में एक दिवसीय अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की बंगाल कमिटी ने किया जिसका संचालन केन्द्रीय सचिव मण्डल के सदस्य साथी हाफिज आलम सैरानी और

कोलकाता जिला पार्टी महासचिव साथी मोइनुद्दीन शम्स ने अन्य साथियों के साथ मिलकर किया।

पश्चिम बंगाल, जहाँ मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या लगभग 24 प्रतिशत है, सहित भारत के मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन और उनके शोषण और गरीबी के सवाल पर उनके जीवन स्तर में सुधार के लिये अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने लगातार आन्दोलन करने की घोषणा की। तथाकथित 8 अगस्त 2009 का सम्मेलन राष्ट्रव्यापि जन सम्मेलन करने के श्रृंखला के तहत था।

सम्मेलन में सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि अल्पसंख्यकों को संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत शिक्षा और रोजगार, राजनीतिक सशक्तिकरण, विधायी निकायों आदि में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये। सम्मेलन ने यह प्रश्न उठाया किया, जब अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान है तो अल्पसंख्यक जो बहुत नीचे स्तर पर है उन्हें उठाने के लिये कोई प्रावधान क्यों नहीं बना। सम्मेलन में मांग उठाया गया कि संवैधानिक पीठ में भेदभाव के लिये सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाना चाहिये। सम्मेलन में यह भी मांग किया कि उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाये, जो कि पश्चिम बंगाल की लगभग 18 से 20 जनता उर्दू भाषा का प्रयोग करती है। राज्य सरकार को उर्दू भाषा की संस्कृति के विकास के लिये पर्याप्त मान्यता देनी चाहिये।

सम्मेलन में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अस्मरणीय क्षणों पर प्रकाश डाला गया जो उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान और शानदार भूमिका के लिये कही थी।

दिशाहीनता ग्रसित शिक्षा

जयंत वर्मा, प्रधान संपादक नीतिमार्ग

वर्ग विशेष के हिमायती लोगों की सरपरस्ती में बने भारत के संविधान में आम नागरिकों की बुनियादी जरूरतें रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन आदि को इज्जत से हासिल करने के लिये रोजगार के अधिकार को मूल-अधिकार में शामिल नहीं किया गया। संविधान के भाग-चार में शासन के मूलभूत तत्व लिपिवद्ध किये गये किन्तु सुशासन सुनिश्चित करने के लिये न्यायपालिका के दरवाजे बंद कर दिये गय। विधायिका पर यह दायित्व सौंपा गया कि वह सुशासन सुनिश्चित करेगा। समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामूहिक हित साधन की दृष्टि से बांटने के प्रावधान के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत के बने उन कानूनों को रद्द नहीं किया गया जो जल, जंगल और जमीन को जनता से छीनने के लिये बनाये गये थे। मजदूर और किसान, दस्तकार, कारीगर आदि के लिये व्यक्तिगत निर्वाह की मजदूरी और निकम्मी नौकरशाही पर सवार लोगों को परिवार के भरण पोषण योग्य वेतन की मानवाधिकार विरोधी नीति अपनाई गयी। गरीब का खून चूसकर 5 प्रतिशत धन्नासेठों और उनकी चाकरी करने वाले 15 प्रतिशत लोगों को खुशहाल बनाने की सोची समझी नीति अपनाकर आजादी के 60 वर्ष बाद भारत को विश्व के सर्वाधिक निर्धन लोगों का देश बना दिया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 83 करोड़ लोग 20/- प्रतिदिन से कम आय पर गुजारा करने को मजबूर है।

संविधान का संशोधन कर 2002 में अनुच्छेद-21 (क) के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया किन्तु इसे अमली जामा पहनाने का दायित्व विधायिका पर डाल दिया गया है। रो-रोकर हाल ही में संसद ने शिक्षा के अधिकार का कानून पारित किया है। इसके लिये संसाधन का अभाव होने के कारण निजी क्षेत्र के सहयोग से पाठशालायें खोलने का रास्ता निकाला गया है।

अमेरिका पूँजीवादी देश होने के बावजूद वहाँ नि:शुल्क विद्यालय की व्यवस्था है। बेहतर संचालित शालाओं के आसपास मकानों के दाम अधिक होते हैं। भारत में सड़ांध वाली पूँजीवादी व्यवस्था है। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया तो प्रत्येक कर पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाने लगा। अर्थात् सबको शिक्षा देने के लिये समाज धन जुटाये और सरकार दलाली खाये। राजकोष का सारा धन निर्माण कार्यों पर खर्च किया जाता है ताकि लोहा, सीमेन्ट, भवन सामग्री निर्माताओं, ठेकेदारों की जेबें भरें। अब शिक्षा के अधिकार को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी भी समाज पर डाल दी जायेगी। 70 फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रही है, वहाँ शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है।

वास्तव में कल्याणकारी राज्य वह कहलाता है, जिसमें आम नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने योग्य जरूरतें पूरी करने सभी को रोजगार मिले। राज्य बहुत कम शुल्क पर सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, यातायात, ऊर्जा एवं सूचनायें उपलब्ध करे। वर्तमान व्यवस्था के तहत भारत को वास्तव में कल्याणकारी राज्य बनने में एक करोड़ से भी अधिक वर्ष लगेंगे। कल्याणकारी राज्य होने का भ्रम फैलाने में ही हमारी व्यवस्था की सारी शक्ति लग रही है।

आश्चर्य तो यह है कि भारत शिक्षा का उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं है। आजीविका के लिये हुनर सीखना और शिक्षत होना बिलकुल अलग है। भारत में पढ़े-लिखे अशिक्षित तैयार किये जा रहे हैं। साथी मानव के साथ भाईचारापूर्ण बर्ताव करने का गुण, समूची सृष्टि को समग्रता से देखकर स्वयं को उसका एक अंग मानकर तद्नुसार जीवन पद्धति अपनाने का गुण, जीवन के उद्देश्य को समझकर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तत्पर रहने का गुण तथा विश्व बंधुत्व अथवा वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से ओत-प्रोत व्यक्तित्व का निर्माण करना ही शिक्षा का मूल लक्ष्य होना चाहिये। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पाठशालायें और महाविद्यालय अंग्रेजी हुकूमत की शिक्षा नीति की उपज हैं। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थायें शासकवर्ग के हित में संचालित होती हैं। ऐसी शिक्षा ने भारत को गर्त में ढकेल दिया है। नौकरी न मिले तो शिक्षा निरर्थक हो जाती है।

मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के अनुच्छेद-26 में शिक्षा का उद्देश्य दर्ज है। भारत में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून बनने के

बावजूद शिक्षा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की संभावना बिल्कुल नहीं दिखती। ऐसे देश का भविष्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता, जिसमें शिक्षा दिशाहीनता से ग्रसित हो, यह हालात निराशापूर्ण है। ईश्वर इस देश के हुक्मरानों को सद्बुद्धि दे यही प्रार्थना की जा सकती है।

– साभारः नीति मार्ग

वाम दलों का जन्तर मन्तर पर महँगाई पर सख्ती से रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन

फारवर्ड ब्लॉक, सीपीआई, सीपीएम और आरएसपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खाद्य सामग्रियों और आवश्यक वस्तुओं के दामों हो रही बेतहाशा वृद्धि, जिसके कारण आम गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, के खिलाफ नई दिल्ली में जन्तर मन्तर पर साझा धरना व प्रदर्शन किया। वे सभी जन्तर-मन्तर पर एकत्रित हुये और संसद की ओर कूच किया। इस प्रदर्शन का संचालन चारों पार्टियों के राष्ट्रीय और राज्य नेताओं ने किया। यह प्रदर्शन वाम दलों का बढ़ती महँगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापि आन्दोलन करने के कार्यक्रम के तहत एक हिस्सा था।

प्रदर्शनकारियों को नेताओं ने सम्बोधित किया। वक्ताओं ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि की जाँच करने में नाकाम रहने के लिये सरकार की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि दालों की कुछ किस्मों की कीमतें बढ़कर 80 से 100 रुपये तक हो गयी है तथा खाद्य तेल, सब्जी, चावल की कीमतों में वृद्धि, गेहूँ आदि की कीमत इतनी हो गयी है कि गरीब परिवारों के लिये इसे खरीदना नामुमकिन सा होता जा रहा है। इसके अलावा बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है और इस स्थिति में महिलाओं के लिये इन वस्तुओं को खरीद पाना मुश्किल होता जा रहा है।

इसके अलावा उन्होंने बताया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाकर वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाने के चलन को अपना लिया है। राज्यों के कई जिलों में सूखे की स्थिति की संभावनाओं के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतें और भी बढ़ गयी है।

मुख्य रूप से प्रदर्शन को साथी ए.बी. वर्धन – महासचिव सीपीआई, साथी प्रकाश करात – महासचिव सीपीएम, साथी अबानी राय, सांसद – आरएसपी, और साथी जी. देवराजन – राष्ट्रीय सचिव फारवर्ड ब्लॉक ने सम्बोधित किया।

प्रदर्शकारियों की मुख्य मांगें निम्न थीः

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दाल और खाद्य तेल रियायती दरों पर उपलब्ध करायी जाये।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्निर्माण कर बीपीएल कार्ड धारकों को बढ़ाया जाये तथा एपीएल श्रेणी को अंतरिम माप करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक किया जाये।
3. पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को वापिस लिया जाये।
4. भविष्य सभी खाद्य सामग्रियों से सम्बन्धित वस्तुओं में व्यापारीकरण पर रोक लगायी जाये।

सुभाष चन्द्र बोस और आज के युवक

30 जुलाई 2009 को नेताजी सुभाष फाउण्डेशन, लंदन, और भारतीय उच्चायुक्त लंदन के सांस्कृति मंच नेहरू सेन्टर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वार्षिक संगोष्ठी के आमंत्रण पर डॉ. बरूण मुखर्जी, सांसद एवं ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय सचिव ने संगोष्ठी में भाग लिया। डॉ. बरूण मुखर्जी ने 'नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और आज के युवक विषय पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया।

लंदन में हाउस ऑफ कमीशन के सांसद श्रीमान विरेन्द्र शर्मा और अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के श्रीमान चन्द्र बोस ने भी इस अवसर पर अपने-अपने वक्तव्य दिये। इस अवसर नेताजी सुभाष फाउण्डेशन, लंदन की ओर से सुश्री माधुरी बोस ने स्वागत भाषण दिया, फाउण्डेशन के संयोजक श्रीमान सुभाष खाले ने इस समारोह की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम को देखने व सुनने वाले श्रोताओं का तांता लगा हुआ था।

साथी बरूण मुखर्जी ने अपने वक्तव्य में 'नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और आज के युवक' विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। जिसका संक्षिप्त रूप से विवरण इस प्रकार हैः-

1. पिछली शताब्दी के 20वें और 30वें दशक में देश की आजादी के संघर्षों के समय में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस युवाओं के सबसे चहेते नेता थे। दूर दराज मंडाला जेल में तीन साल की कठोर कारावास के बाद (1924-1927) जब सुभाष चन्द्र बोस बाहर आये तो उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था लेकिन फिर भी देश की आजादी के लिये अपनी तैयारियों में लग गये। 21 दिसम्बर 1929 को सुभाष बाबु ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा 'मैं एक राज्य और एक ऐसा समाज चाहता हूँ जो हम भारतीयों की सभी जरूरतों को पूरा करता हो और पूरी दुनिया में एक आदर्श बन जाये'।

सुभाष बाबु को यह दृढ़ विश्वास था कि देश का भाग्य युवाओं पर निर्भर है। अत:, उनके आजादी के आंदोलन की योजना और क्रियाशीलता में युवाओं का विशेष महत्व होता था। सुभाष कहते थे 'युवा आंदोलन का दृष्टिकोण दिखने में क्रांतिकारी होता है लेकिन वह सुधारवादी होता है। वर्तमान व्यवस्था को देखते हुये वह बेचैन हो उठता है और उसमें असंतोष की भावना जागृत हो जाती है जिससे वह युवा अपना आन्दोलन आरम्भ कर देता है... यह उसकी असंतोषजनक भावनाओं का ही असर होता है जो वर्तमान अव्यवस्था से जागरूक होती है।'

आज 80 वर्षों के पश्चात् भी युवाओं में इसी तरह विशेषता अब भी बनी हुयी है। उसी प्रकार की असंतोषजनक भावना वर्तमान व्यवस्था के कारण उसमें जागृत है। सुभाष चन्द्र बोस के आदर्श और आजादी के लिये संघर्ष की भावना आज भी उतने ही फायदेमंद है जितना पहले थी।

यदि हम पिछले दिनों की तुलना करें तो आज ज्ञान के क्षेत्र में युवाओं संपर्क काफी व्यापक और तेज है। ज्ञान पाने की जिज्ञासा और प्यास उसके कार्यान्वयन के लिये उसकी इच्छा को बढ़ा को देती है, उसके कार्यान्वयन के लिये जब वह देखता है कि उसका कोई ईलाज नहीं है तो उसे यह बात निराश कर देती है।

लंदन शहर भारतीय राजनीतिक सम्मेलन 1993 में आयोजिक भारतीय राजनीतिक सम्मेलन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि 'आजाद भारत पूँजीपतियों, भू-स्वामियों और जातिवादियों की धरती नहीं होगी।

हमे सुभाष बाबु के उनके एक अलग ही राजनीतिक व्यक्तित्व और विचारों को नहीं भूलना चाहिये। उन्होंने कहा था कि हमारे युवाओं को आज राष्ट्र निर्माण का कार्य करने में लग चाहिये

सुभाष चन्द्र बोस ने 26 मई 1931 को मथुरा में आयोजित सम्मेलन में कहा था कि भारत में समाजवाद की स्थापना पाने के लिये उन्होंने कहा था 'एक समाजवाद के दर्शन के लिये इन पाँच सिद्धांतों को जीवन में उतारना जरूरी है - न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन और प्यार। उन्होंने आगे कहा था कि इन पाँच सिद्धांतों के आधार पर समाजवाद की स्थापना भारत में स्थापित होते देखना चाहते है। ये पाँचों सिद्धान्त आज के युवा को अपनी समस्याओं को समझने में काफी मदद कर सकते है और उनके प्रेरणा स्रोत बन सकते है।

बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम

त्रि-देशीयद कमिटी गठित (हेड क्वार्टर ढाका में)

बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम (भारत चैप्टर) ने भारत छोड़ो/अगस्त क्रान्ति आन्दोलन के 67 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में कोलकाता में 12 अगस्त से 17 अगस्त 2009 तक का 6 दिवसीय त्रि-देशीय बैठक का आयोजन किया।

कार्यक्रम का आयोजन कोलकाता के आस-पास अलग-अलग क्षेत्रों में किया गया, जैसे कोलकाता प्रेस क्लब, ग्रीन कोटेज हॉल इकबालपुर, सोनपुर के होगोलबेरिया और तेगोरिया में मुस्लिम इन्सटिट्युट हॉल, नेताजी सुभाष लायब्रेरी, लेनिन सरानी, मेट्रो चैरल, पलासी और मुर्शीदाबाद।

बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रतिनिधी कोलकाता में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में समाज के सभी स्तर के लोगों से मिले।

सम्मेलन में कोलकाता घोषणा प्रस्ताव ग्रहण किया गया। यह महीना वह महीना है जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी हत्याकाण्ड हुआ है और इसी माह में 62 वर्ष पूर्व भारत का विभाजन हुआ था, इस विभाजन का कारण हम लोगों के लिये आज तक एक प्रश्न बना हुआ है। तीनों देशों की जनता का मानना है कि विभाजन, समस्या का समाधान नहीं हो सकता बल्कि इससे विवाद और बढ़ता है और दिन प्रतिदिन इन 62 वर्षों में बढ़ा ही है। और यह विवाद है, आतंकवाद, पानी का अंश, सीमा विवाद, कटीली तारों की बाढ़, नकली मुद्रा, नागरिकता का अंत:स्पंदन के मामला और अवैध व्यापार आदि।

सम्मेलन में दृढ़ मत के साथ घोषित किया कि तीनों देशों के बीच जो विवाद है उसे सिर्फ तीनों देशों में शान्ति चाहने वाली जनता की मध्यस्थता से ही दूर किया जा सकता है, न कि अफसरशाही तरीके से या किसी चौथे देश के दखलअंदाजी से।

बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम इस त्रि-देशीय इस मंच को एक अधिकारिक स्थायी मंच बनाने का निवेदन करता है जिससे सब कुछ एक शांतिपूर्ण और लंबी बातचीत में हल किया जा सके और इसके प्रस्तावों, कार्यक्रमों और निर्णयों में किसी चौथे देश का दखलअंदाजी न हो और यह मंच गंभीरता से एक मजबूत जन मंच बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी अन्य चौथे देश के दखलअंदाजी के बिना ही प्रस्तावित अधिकारिक मंच को तीनों देशों के बीच सहायता और मदद कर सके।

इस संदर्भ में त्रि-देशीय सम्मेलन का निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करता है:

1. दमनकारी और तोड़फोड़ की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ इन तीनों देशों में लोकतंत्र, समाजवाद, सद्भाव और शांति के लिये जारी शांतिप्रिय जनता के संघर्ष को और मजबूत बनाना होगा।
2. इन तीनों देशों के बीच वीजा प्रतिबंधों, डाक और दूरसंचार शुल्क आदि सेवाओं को सामान्तर और सरल बनाया जाना चाहिये।
3. इन तीनों देशों में किसी भी आतंकवादी बल के परिचालन को बढ़ावा देने से रोक लगानी चाहिये।

बांग्लादेश–भारत–पाकिस्तान पिपुल्स फोरम ने एक 10 सदस्यीय त्रि–देशीय कमिटी का निर्वाचन किया, जिसमें 6 सदस्य कार्यालय सचिव मंडल के रूप में चयनित किये गये। जिसमें श्री मोईनुद्दिन खान बादल – महासचिव (बांग्लादेश), श्री देवब्रत बिश्वास – अध्यक्ष (भारत), मोहम्मद दवाज अरायन – कोषाध्यक्ष (पाकिस्तान) से आदि चयनित किये गये।

शिक्षा के व्यापारीकराण के खिलाफ राष्ट्र व्यापि आन्दोलन की आवश्यकता है।

नई दिल्ली में शिक्षा सम्मेलन का आयोजित

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के शिक्षा विभाग ने 'शिक्षा – एक जनतांत्रिक मुद्दा' पर 20 अगस्त 2009 को बंग भवन, नई दिल्ली में एक वाद–विवाद सम्मेलन का आयोजन किया।

साथी नरेद दे, माननीय कृषि मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार, ने इस समारोह की अध्यक्षता की। साथी (डॉ.) बरूण मुखर्जी, सांसद एवं अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के केन्द्रीय समिति के शिक्षा विभाग के इंचार्ज ने इस प्रसंग का दस्तावेज प्रस्तुत किया। प्रसंग दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये साथी मुखर्जी ने शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे देश के लिये हानिकारक सिद्ध होने वाले आर्थिक सुधारों के बारे में जन जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं सीपीएम के दिल्ली राज्य कमिटी के सचिव प्रो. विजेन्द्र शर्मा इस चर्चा के मुख्य वक्ता थे। उन्होंने अलंकृत यशपाल कमिटी की नाकारात्मक पहलुओं और संप्रग के दूसरे दौर में सरकार के 100 दिनों के एजेंडा के बारे को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया की विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस आरम्भ हो जाने से हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली तहस–नहस हो जायेगी। इसके अलावा तीसरे या चौथे दर्जे के विदेशी विश्वद्यालय ही पैसा कमाने के उद्देश्य से भारत में आने के लिये तैयार हुये है। उन्होंने केन्द्र सरकार से शिक्षा के साथ एक वस्तु जैसा व्यवहार न करने का आग्रह किया।

प्रो. अमर सिंह कुशवाहा ने शिक्षा की अंधाधुंध निजीकरण के सामाजिक प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने व्यवसायिक शिक्षा में चल रहे भ्रष्टाचार को एक के बाद एक कई व्याख्या की। साथी वी.पी. सैनी ने बताया कि इस आधुनिक शिक्षा में देशभक्ति की भावना न के बराबर है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली इंसान को भावना रहित और बिना समझ वाली एक मशीन बना रही है। डॉ. बी.डी. शर्मा ने मिड–डे मिल योजना में जारी कुप्रबंधन के बारे में कई पहलुओं को बताया।

साथी नरेन दे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ व्यापक राष्ट्र व्यापी जन आंदोलन को दाहराया और कहा कि की देश के वामपंथी दलों और समाज के प्रगतिशील जनता को इस आंदोलन को आरम्भ करना चाहिये। डॉ. बिथिका मंडल, विधायक, प्रो. गौरिका घोष, डॉ. एस.के. बिश्वास, राम प्रसाद शुक्ला आदि ने भी इस चर्चा में भाग लिया। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथी जी. देवराजन धन्यवाद प्रस्ताव देते हुये कहा कि यह चर्चा जागरूकता लाने के सम्बन्ध श्रृंख्लावद्ध योजनाओं के तहत अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की ओर से यह एक शुरूआत है।

चर्चा में प्रस्तुत प्रसंग दस्तावेज निम्न है:

वादविवाद सम्मेलन

शिक्षा – एक जनतांत्रिक मुद्दा

ॐ शिक्षा में सुधार के नाम पर शिक्षा में विदेशी सम्बन्धों और निजीकरण को बढ़ावा देना बन्द करो।

ॐ सभी के लिये मुफ्त और उत्तम शिक्षा निती लागू की जाये।

1. यह एक बहुत ही चिंता का विषय है कि केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने अपना कार्यभार संभालने के तुरन्त बाद 100 दिनों के कार्यक्रम की दलील पर शिक्षा से सम्बन्धित काल्पनिक घोषणाये करना आरम्भ कर दिया, जो उनके गलत अवधारणाओं और मनमानेपन को दर्शाता है, जिनसे हमारी शिक्षा प्रणाली को गम्भीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि शिक्षा हमारे संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है फिर भी हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री इन तथाकथित सुधारात्मक घोषणाओं से पूर्व विशेषज्ञों एवं राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करने की आवश्यकता को महसूस नहीं करते है। इन तथाकथित सुधारों से न केवल वर्तमान शिक्षा प्रणाली को नुकसान होगा बल्कि लाखों एवं करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्री ने घोषणा की है कि दसवीं अथवा माध्यमिक परीक्षा को समाप्त कर दिया जाये जो कि ऐसी पहली परीक्षा है जो सार्वजनिक है और इसकी बजाय विद्यार्थियों को यह सलाह देती है कि सीधा बारहवीं कक्षा की परीक्षा में बैठ जाओ। दुर्भाग्यवश मंत्री जी को यह पता नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में गरीब विद्यार्थी बारहवीं कक्षा तक जा ही नहीं सकते। वे

माध्यमिक सर्टिफिकेट से ही संतुष्ट हो जाते है और विभिन्न क्षेत्रों में अपेन लिये स्थान ढूँढने की कोशिश करते है। मानव संसाधन विकास मंत्री की यह मुर्खता भरी योजना निर्धन विद्यार्थियों को उनके भविष्य के अवसरों से वंचित करवा देगी। मानव संसाधन विकास मंत्री की अजीब योजना का एक और उदाहरण है स्कूल वाउचर (स्कूल रसीद)। इस वाउचर योजना का अर्थ है कि सरकार स्कूलों के लिये धन उपलब्ध नहीं करवायेगी। इसकी बजाये वह परिवारों को वाउचर के रूप में सीधे धन देगी। बच्चों के अभिभावक अपने मन पसन्द के स्कूलों से इन वाउचरों का भुगतान ले लेंगे। यह वाउचर योजना अमेरीका के मिलवाउकी में किया गया एक पुराना प्रयोग है। जिसके अनुसार इसे केवल 15 प्रतिशत विद्यार्थियों तक ही पहुँचा जा सका। अधिकतर लोगों ने मानव संसाधन विकास मंत्री के इस बेतुके प्रस्ताव को नकार दिया है।

2. संप्रग सरकार की शिक्षा नीतियों की मुर्खता का पर्दाफाश तब हो जाता है जब वह शिक्षा के अधिकार के बड़े-बड़े दावे करे है परन्तु दुर्भाग्यवश इसके लिये बजट में बहुत कम पैसे का प्रावधान करते है। 2009-10 के बजट में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये खर्च में केवल 200 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु की बच्चों को शिक्षा अधिकार सुनिश्चित करने के लिये काफी नहीं है। संप्रग सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6 प्रतिशत शिक्षा के लिये खर्च करने का वायदा वास्तविकता से कोसों दूर है। यह सरकार पहले ही शिक्षा के लिये विशेषकर आरम्भ में 2 प्रतिशत और बाद में 1 प्रतिशत लगा चुकी है। हमें इस बात का डर है कि शिक्षा के अधिकार के नाम पर सरकार विशेष शिक्षा कर थोप सकती है। यह सब बातें दर्शाती है कि सरकार शिक्षा के मुद्दे पर गम्भीर नहीं है।

3. सभी को शिक्षा, वह भी मुफ्त और उत्तम शिक्षा, जो कि आज के समय की मांग है, इसको शब्दों में नहीं, वास्तविकता में लागू करने की जरूरत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि अभी भी हमारी जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा साक्षरता के ज्ञान से महरूम है।

वास्तव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार की नियत कुछ और ही है। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सभी कोशिशों का उद्देश्य एक विशेष अधिकारों वाले समाज की स्थापना करना है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में भी धनवान और निर्धन के बीच का अन्तर स्पष्ट नजर आ जाये। संप्रग सरकार का शिक्षा में श्रेष्टता कार्यक्रम जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, का उद्देश्य भारत में विश्व स्तरीय आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है, परन्तु दुर्भाग्यवश यह इतनी महँगी है कि हमारे देश के बहुत कम अमीर लोग ही इसका लाभ उठा सकते है। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा इतनी महँगी शिक्षा पाने का स्वपन भी नहीं देख सकता। हमारे समाज में अलग-अलग युवा वर्ग के लिये विभिन्न प्रकार की शिक्षा की सुविधायें समाज के निर्धन और अमीर वर्ग के बीच की खाई को और बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार की शिक्षा नीतियों से संप्रग सरकार उस सम्पूर्ण विकास को कभी प्राप्त नहीं कर पायेगी जिसका वह इतना प्रचार कर रही है। हम शिक्षा में विकास के विरोधी नहीं है, परन्तु इसके लिये हम सबके लिये मुफ्त और गुणात्मक शिक्षा की आवश्यकता को नजर अंदाज नहीं कर सकते।

4. संप्रग सरकार का वास्तविक उद्देश्य तो कुछ और है। शिक्षा में विकास के नाम पर यह शिक्षा के क्षेत्र में विदेशों के साथ समझौते और बहुत बड़े स्तर पर निजीकरण करना चाहती है। जुलाई 2009 में अमेरिका की विदेश मंत्री हिलैरी क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान दो सरकारों के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं। भारत के विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा एवं अमेरिका की विदेश मंत्री श्रीमती हिलैरी क्लिंटन ने समझौते पर हस्ताक्षर करके इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सम्बन्धों में सुधार के लिये आपसी आदान-प्रदान एवं संस्थानों में अधिक सहयोग किया जाये और इस मिलवरतन को सुदृढ़ करने के लिये निजी क्षेत्र में अधिक विकास किया जाये।

5. शिक्षा के निजीकरण और विकास के बढ़ते रूझान के विरुद्ध केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि इंग्लैण्ड और दूसरे विकसित देशों में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। लंदन में छपने वाले समाचार पत्र द-ऑब्जरवर' में 26 जुलाई 2009 को 'निजी स्कूलों में असमानता दूर करो' सरलेख से एक पत्र प्रकाशित हुआ था।

"विद्यार्थियों को जीवन में अच्छा स्थान पाने के लिये तैयार करने की बजाय निजी स्कूल विशेष शिक्षा के नाम पर श्रेष्ठता को बढ़ावा दे रहे है। दाव पर जो लगा है वह शिक्षा नहीं पहचान है। यदि ऐसे किसी विशेषाधिकार वाले सदस्य को उसके बोलने के अन्दाज, वर्दी, रिवाज, डॉक्टर, वकील, राजदूत आदि की पहचान से अलग कर दिया जाये तो वह क्या होगा ?किसी भी दूसरे साधारण इन्सान जैसा सोचा भी नहीं जा सकता, जिनमें श्रेष्ठता की गलत फहमी है, जिनमें भावनाओं का कोई निवास नहीं है, जिनकी सोच केवल इस तथ्य पर आधारित है कि - मैं यह जानता हूँ कि मेरा पालन पोषण यहाँ हुआ। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को इस दुनिया में रहने के लायक बनाना है न कि इससे नफरत करना। यह कैसे हो सकता है जब उन्हें एक ऐसी व्यवस्था में अलग-थलग कर दिया जाता है, जो हमारी पुरानी शाही पारम्परिक शाही सम्मानित संस्कृति की कीमतों के साथ जुड़ी हुयी है।

6. प्रो. डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता वाले शिक्षा आयोग (1964-1966) ने भी अपनी रिपोर्ट जो, 1966 में पेश की गयी थी ऐसे ही विचार व्यक्त किये थे। दुर्भाग्यवश संप्रग सरकार ने इन सुधारों की जल्दबाजी में घोषणा करते समय इस आयोग की रिपोर्ट के सुझावों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा ''हमारी राय में कोई भी सुधार इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि शिक्षा में ऐसा परिवर्तन लाना जिससे ये जीवन के साथ जुड़ सके, लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके ऐसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन ला सके, जिससे हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।''

हम कोठारी आयोग (1964-66) की कुछ ऐसी ही टिप्पणियों का भी यहाँ जिक्र कर सकते हैं जो संप्रग सरकार द्वारा शिक्षा सुधारों के नाम पर शिक्षा संकट पैदा करने के परिप्रेक्ष्य में प्रसंगानुकूल है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार:

(क) ''सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण एक प्रमुख समस्या है, जिसके समाधान के लिये कई उपाय करने पड़ेंगे जिनमें से एक शिक्षा भी है। हमारे विचार में इस काम में शिक्षा को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिये जिसके लिये सार्वजनिक शिक्षा के लिये एक सांझी स्कूल प्रणाली तथा समाज और राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा के सभी स्तरों पर एक अभिन्न अंग बनाना चाहिये।''

(ख) ''जिस प्रकार की स्थिति आज भारत में है, उसमें शिक्षा प्रणाली की यह जिम्मेवारी है कि वह समाज के विभिन्न वर्गों और श्रेणियों को इकट्ठा करें और संगठित समाज की स्थापना करें। परन्तु वर्तमान समय में ऐसा करने की बजाये शिक्षा सामाजिक अलगाववाद को बढ़ावा दे रही है और सामाजिक भेदभाव को बढ़ा ही नहीं रही बल्कि इसे मजबूती प्रदान कर रही हैं। प्रारम्भिक स्तर पर मुफ्त शिक्षा देने वाले इन स्कूलों, जहाँ आम जनता अपने बच्चों को भेजती है का रख-रखाव सरकार अथवा स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है और आमतौर पर यह निम्न स्तर के होते हैं। कुछ निजी स्कूल निश्चित तौर पर अच्छे है परन्तु क्योंकि उनमें से अधिकतर ज्यादा फीस लेते हैं, उनका लाभ मध्यम और उच्च श्रेणी के लोगों द्वारा ही उठाया जाता है। माध्यमिक स्तर पर बड़े अनुपात में अच्छे स्कूल निजी है परन्तु उनमें से अधिकतर फीस लेते हैं जो कि समाज के 10 प्रतिशत समूह वर्ग को छोड़कर बाकियों की पहुँच से दूर है। यद्यपि मध्यम वर्ग के कुछ लोग कुर्बानी करके अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिये भेजते हैं इसलिये अलगाव शिक्षा में ही है - कम गिनती में निजी, फीस लेने वाले अच्छे स्कूल जो कि ऊपर वाली श्रेणी के लोगों की जरूरत को पूरा करते है और बड़ी गिनती में मुफ्त शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूल जिनका लाभ अधिकतर जनता उठाती है। जो बात और भी बुरी है वह यह है कि यह अलगाव बढ़ रहा है और अलग-अलग श्रेणियों तथा समूहों में दूरियों को बढ़ा रहा है।''

(घ) वर्तमान शिक्षा प्रणाली की यह सबसे बड़ी कमजोरी है। सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बजाय अथवा समाज के हर वर्ग के योग्य बच्चों को शिक्षा देने की बजाये यह एक बहुत ही कम गिनती को उपलब्ध है जिसे आमतौर पर योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि फीस देने की क्षमता के आधार पर चुना जाता है।

(ङ) यदि हमें इन बुराईयों को समाप्त करना है और शिक्षा को साधारणतया राष्ट्रीय विकास का एक शक्तिशाली साधन बनाना है और विशेषतौर पर सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण का साधन बनना है, तो हमें सार्वजनिक शिक्षा में एक ऐसी सांझी स्कूल प्रणाली के लक्ष्य की ओर बढ़ना है -

- जो जाति, नस्ल, समाज, धर्म, आर्थिक एवं सामाजिक हैसियत के भेदभाव के बिना सबको उपलब्ध होगी
- जहाँ अच्छी शिक्षा धन और श्रेणी के आधार पर नहीं बल्कि विशिष्ट मानसिक योग्यता के आधार पर होगी। जिसमें सभी स्कूलों में काफी अच्छा स्तर रखा जायेगा और तर्कपूर्ण अनुपात में अच्छे स्कूल बनाये जायेंगे, जिसमें कोई फीस नहीं ली जायेगी।
- जो औसत अभिभावकों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ताकि उनको अपने बच्चों को प्रणाली के बाहर महँगे स्कूलों में भेजने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी।

5. ऐसी ही एक शिक्षा प्रणाली यू.एस.एस.आर. में विकसित की गयी है वहाँ की प्रगति में योगदान डालने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारण है। ऐसी ही व्यवस्था विभिन्न स्वरूपों में और अलग-अलग सीमाओं तक अमेरिका, फ्रांस तथा स्कैंडीनावीयन देशों में भी विकसित की गयी है। परम्परागत इंगलिश प्रणाली अलग प्रकार की है जिसमें निजी प्रबन्धकों द्वारा अच्छी शिक्षा इन लोगों को देने की व्यवस्था हैं जिनमें आवश्यक फीस देने की समर्थता है। परन्तु पिछले कुछ समय में इंग्लैण्ड में भी तथाकथित पब्लिक स्कूलों की कड़ी आलोचना हुयी है और ऐसा सम्भव है कि उनको अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिये उनमें कुछ आमूल सुधार किये जाये। ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा भारत में भी एक लगभग ऐसी ही प्रणाली को स्थापित किया गया और हम अभी तक इसके साथ चिपके हुये हैं क्योंकि यह हमारे समाज की पारंपरिक सौपानिक संरचना से मेल खाता है। इसका प्राचीन इतिहास कुछ भी हो सकता है परन्तु जिस लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज की रचना करने की हमारी इच्छा है, उसमें इसका कोई स्थान नहीं है।

6. हमारे परम्परागत समृद्ध लोगों का - कुछ भद्र पुरूषों को छोड़कर - आम जनता के साथ कुछ घनिष्ठ समन्वय नहीं थे और आधुनिक शिक्षा द्वारा तैयार की गयी नई विशिष्ट श्रेणी भी आम जनता से काफी अलग-थलग है।

7. इस उद्देश्य के लिये हम इस बात की सलाह देते हैं कि सभी विद्यार्थियों के लिये किसी न किसी रूप में सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य की जानी चाहिये और सभी स्तरों पर शिक्षा का एक अभिन्न अंग बना दिया जाना चाहिये। यह चरित्र निर्माण, अनुशासन सुधार के साथ-साथ शारिरीक श्रम करने वालों के प्रति सम्मान की भावना तथा सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करने का एक जरिया बन सकता है। सुभाष चन्द्र बोस का भी नौजवान पीढ़ी में शिक्षा के माध्यम से देशभक्ती की भावना पैदा करने का यही मतलब था।

दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत होता है कि संप्रग सरकार ने इस योग शिक्षा आयोग की इन टिप्पणियों और सिफारिशों को नजर अंदाज कर दिया है और राष्ट्र पर अपना बहुत ही नुकसान पहुँचाने वाला कार्यक्रम को जबरदस्ती लागू करने का मन बना लिया है।

7. हमें इन दिनों संप्रग सरकार द्वारा आरम्भ किये गये शिक्षा सुधारों में एक और खतरनाक पहलू की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले दिनों सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक गम्भीर चाल चली है जिसके मुताबिक अमेरिका के साथ सम्बन्ध बनाने हैं। जबकि सरकार अभी बड़े गर्व के साथ विदेशी विश्वविद्यालय बिल लाने की योजनाओं की घोषणा कर रही है वहीं दूसरी ओर वे अमेरिका के अधिकारियों के साथ अमेरिकन विश्वविद्यालयों को अपने परिसर भारत में बनाने के समझौतों को अनुमति दे चुके हैं। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल और अमेरिका के विदेश मंत्रालय के राजनैतिक मामले के सह–सचिव वी. विलियम बर्न्ज ने 11 जून 2009 को नई दिल्ली में मुलाकात की और एक साझा कार्यक्रम ग्रुप नियुक्त करने का निर्णय लिया जो दोनों देशों के दरमियान शिक्षा के सम्बन्धों की निगरानी करेगा। सिब्बल और बर्न्ज दोनों इस बात पर सहमत थे कि यह ग्रुप लगभग अन्य 30 देशों के साथ बनाये गये ऐसे ग्रुपों से भिन्न होगा। यह ग्रुप भारत में अमेरिका द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले निवेश में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और ऐसे निवेश का नियंत्रण करने वाले कानूनों को नई शक्ल देने में भी भूमिका अदा करेगा।

इस समय भारत द्वारा विदेशों में भेजे जाने वाले विद्यार्थियों में से सबसे ज्यादा अमेरिका में जाते हैं जिनकी संख्या लगभग 90,000 प्रति वर्ष है। नई योजना के मुताबिक संप्रग सरकार अब भारत में ही अमेरिकी शिक्षा संस्थान बनाने के लिये निमंत्रण दे रहा है। क्योंकि सिब्बल ने शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिकी निवेश को आमंत्रित करने में गहरी रूची दिखाई है, बर्न्ज ने भी इच्छा प्रकट की है उच्च शिक्षा में विदेशी निवेशकों पर लगी सख्त पाबंदियों को नरम किया जाये। यह जानकारी मिल रही है कि यह कार्य ग्रुप सैकेण्डरी, उच्च तथा व्यवसाय शिक्षा क्षेत्रों में संस्थागत सम्बन्धों पर ध्यान केन्द्रित करेगा। एक ऐसे समय में जब हमारी शिक्षा संस्थायें बहुत ही आवश्यक सुविधाओं से वंचित है, अमेरिका को भारत में शिक्षा परिसर बनाने की अनुमति देने के गम्भीर परिणाम हो सकते है और भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिये यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। ऐसे विदेशी शिक्षा संस्थानों द्वारा जो शिक्षा ज्ञान हमारे नौजवानों को दिया जायेगा उससे हमारे सामाजिक ढाँचे पर भी गम्भीर असर पड़ेगा।

8. इस बात का डर है कि जब एक बार अमेरिकन अथवा दूसरे देशों द्वारा भारत में संस्थापित शिक्षण संस्थान कुछ गिने–चुने विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करनेगा तो उनमे ऐसी सोच और संस्कार पैदा हो जायेंगे जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर और परम्पराओं के विपरीत होगी। हमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की विचारधारा को याद करना चाहिये जिसके अनुसार नौजवान पीढ़ी में देशभक्ती की भावना पैदा करना शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिये। उन्होंने कहा था कि इससे एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका द्वारा जापान में लागू की गयी नई शिक्षा प्रणाली के दुष्परिणामों का बहुत कड़वा अनुभव है, जिससे देश का सारा युवा वर्ग देशभक्तों की भावना और विचारधारा से दूर हो गया था। जापान में अमेरिकन शिक्षा संस्थानों में पढ़े हुये एक ऐसे युवा वर्ग का विकास हो गया जो न तो अपनी मातृभूमि के बारे में जानता था और न ही उससे प्यार करता था। पिछले कुछ समय में जापान को इस गम्भीर खतरे का एहसास हुआ और उसने अपने देश में अमेरिका शिक्षा में बदलाव लाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। आज जापान जिस बात का एहसास कर रहा है, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं कर रहे हैं। वास्तव में वह लोगों द्वारा भारत में अमेरिकन विश्वविद्यालयों के लिये दरवाजे खोलने से संभावित खतरों को समझने में असमर्थ है। इसके उलट वह लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अपनी मानसिक सोच को बदले और भारत में अमेरिकन शिक्षा संस्थानों के परिसरों का स्वागत करें।

इस प्रकार मानव संसाधन विकास मंत्री ने संप्रग सरकार की उस शिक्षा नीति को पूर्ण से व्यक्त कर दिया है जिसके अनुसार शिक्षा में विदेशी निवेश और निजीकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका हैं। हम शिक्षा क्षेत्र में इस खतरनाक परिवर्तन का विरोध करते हैं और विद्यार्थियों, उनके अभिवावकों और अध्यापकों से अपील करते हैं कि वह सभी मिलकर इसके विरूद्ध संघर्ष करें।

फारवर्ड ब्लॉक की तमिलनाडु में ऑफिस का उद्घाटन

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के तमिलनाडु में ओल्ड नं. 8, न्यू नम्बर 23, कान्वेन्ट रोर्ड, केन्टोनमेन्ट, तिरूचीरापल्ली, तमिलनाडु में जिला कमिटी का उद्घाटन किया गया। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के इतिहास में 5 अगस्त 2009 मील का पत्थर बन गया। उद्घाटन समारोह में साथी देवब्रत बिश्वास से सम्बोधित किया।

वोरियुर, तिरूचिरापल्ली में साथी बिश्वास ने पसुम्पन मुथुरामालिंगा थेवर की प्रतिमा पर माला अर्पित किया और ओट्टाकाडाई में पार्टी का झण्डा रोहण किया और पत्थर नक्काशी द्वारा बना पार्टी का बोर्ड का प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर तमिलनाडु राज्य कमिटी के महासचिव पी.वी. कादिरवन, जिला सचिव एडवोकेट ए. जोजफ सागायाराज और पॉण्डिचेरी के महासचिव साथी यू. मुथु भी समारोह में उपस्थित थे।

मदुरै में होटल पर्ल में 6 अगस्त 2009 को तमिलनाडु राज्य सचिव मण्डल और टी.यू.सी.सी. की संयुक्त बैठक हुयी। जिसकी अध्यक्षता साथी देवब्रत बिश्वास ने की। इस बैठक में टी.यू.सी.सी. के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी जी.आर. शिवशंकर और महासचिव एस.पी. तिवारी भी उपस्थित थे।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में पर साथी देवब्रत बिश्वास ने खुशी जाहिर करते हुये अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि तमिलनाडु राज्य इकाई की गतिविधियाँ तेज रफ्तार से दौड़ पड़ी है। उन्होंने बताया कि पार्टी को छद्म प्रकृति के लोगों से बचाकर चलना है और पार्टी को एकता की मजबूत डोर में बाँधे रखना है। पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा और एकल प्रभाव से बचाना होगा। पार्टी में सामूहिक

नेतृत्व को बढ़ाना होगा। उन्होंने बताया कि अगर हम पार्टी के नियम और कानून के अनुसार कार्य करते रहेंगे तो पसुम्पन थेवर और मुकिय्या थेवर के पार्टी के सुनहरे दिनों में वापस लौटेंगे। हमें व्यवस्थित रूप से बढ़ना होगा।

इस कार्यक्रम को सभी समाचार पत्रों, टी.वी. चैनलों ने प्रकाशित किया।

टी.यू.सी.सी. की गतिविधियाँ

पश्चिम बंगाल : 1 अगस्त 2009 को कोलकाता के हेमन्ता बसु भवन में टी.यू.सी.सी. पश्चिम बंगाल राज्य कमिटी की बैठक हुयी। जहाँ सदस्यता अभियान, असंगठित क्षेत्र के सम्मेलनों, आंगवाड़ी श्रमिकों, विभिन्न जूट, इंजीनियरिंग, कपड़ा, बीड़ी, ईंट भट्टा मजदूर, चाय बागान मजदूर, परिवहन आदि के राज्य स्तरीय सम्मेलनों के विषय पर चर्चा की गयी। यह निर्णय लिया गया कि 23 सितम्बर 2009 को कोलकाता में बीड़ी मजदूर सम्मेलन किया जायेगा।

तमिलनाडु : तमिलनाडु राज्य कमिटी की बैठक 6 अगस्त 2009 को मदुरै में संपन्न हुयी। बैठक में राज्य में विभन्न संवैधानिक संगठनों के युनियनों की पंजीकरण, उनके प्रतिनिधित्व आदि के संबंध चर्चा की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि कांग्रेस द्वारा संचालित संप्रग के श्रमिक विरोधी रवैये के तहत एक आन्दोलन किया जायेगा। छंटनी, नौकरी में कमी, कार्य करने का समय निर्धारण आदि के अलावा थिरूपुर और राजापलायम में गारमेन्ट क्षेत्र के श्रमिकों ने निर्णय लिया कि ग्लोबल मंदी के कारण प्रभावित परिवारों को अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिये प्रोत्साहन पैकेज दी जाये।

बिहार : बिहार राज्य कमिटी की बैठक 16 अगस्त 2009 को पटना में आयोजित की गयी। जहाँ राज्य के संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गयी। निर्माण मजदूर, घरेलू और घर आधारित श्रमिकों की सदस्यता पहचान पत्र आदि जारी करने की समीक्षा की गयी। इसके अलावा नवादा, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर के जिला सम्मेलनों पर भी चर्चा की गयी। नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिये दो कार्यशालाओं के आयोजन का प्रस्ताव किया गया जो राजगीर (नालंदा) और मुजफ्फरपुर में अक्तूबर माह में आयोजित की जायेगी। असंगठित मजदूर संगठन, बिहार की विस्तारित कार्यकारिणी समिति की राज्य सम्मेलन 20 सितम्बर 2009 को पटना में आयोजित की जायेगी जिसको साथी एस.पी. तिवारी, महासचिव टीयूसीसी, सम्बोधित करेंगे।

कोलः वेस्ट बंगाल कोलियरी मजदूर यूनियन और अग्रगामी झारखण्ड कोलियरी मजदूर यूनियन का संयुक्त बैठक 3 अगस्त 2009 को सेंक्टोरिया, बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ। सभा में मुख्य रूप से साथी एस.पी. तिवारी, महासचिव टीयूसीसी, नरेन चटर्जी, महासचिव पश्चिम बंगाल राज्य कमिटी, टी.यू.सी.सी., साथी रजत सेनगुप्ता, सचिव टी.यू.सी.सी., साथी माणिक आचार्य, साथी अपर्णा सेनगुप्ता, साथी जनार्दन पाण्डे तथा अन्य साथीगण भी उपस्थित थे। आठवें आई.सी.डब्ल्यू.ए. की जो असंगतियाँ है, उनमें कोयला मंत्रालय का कोयला क्षेत्र को भविष्य में निजीकरण की योजना है, सुरक्षा उपकरणों की अपर्याप्त आपूर्ति करना, बड़े स्तर मजदूरों की छंटनी, भूली क्षेत्र के बीसीसीएल में अपर्याप्त पुनर्उद्धार नीतियाँ प्रशासकीय प्रबंधकीय आदि को मजबूत करने के नाम पर अत्यधिक खर्चा करके घाटा दिखाना आदि बैठक में सभी बातों मजदूरों के सामने इस विस्तृत रूप से पर चर्चा की गयी और कोल मजदूरों को जागरूक करने और कोल प्रबंधन की अनुचित क्रियाकलापों और अलाभकारी नीतियों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।

कोल क्षेत्र की इन सभी विसंगतियों के प्रति विचार विमर्श के लिये टी.यू.सी.सी. के बैनर तले एक सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा, जिसके लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संगठनों के साथ मिलकर एक 15 सदस्यीय स्वागत कमिटी का गठन किया गया।

डिफेन्स : साथी एस.पी. तिवारी, महासचिव टी.यू.सी.सी. और अध्यक्ष एनपीडीईएफ, ने साथी संजय यादव, संगठन सचिव एनपीडीईएफ के साथ कानपुर का दौरा किया। उनका स्वागत विभिन्न डिफेंस क्षेत्र के युनियन संगठनों जैसे ओसीएफ, ओईएफ, एफजीएफ, ओपीएफ आदि के नेताओं ने रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया।

12 और 13 अगस्त 2009 को रक्षा उत्पादन प्रतिष्ठानों के कार्यकारी समिति के नेताओं से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को धैर्य पूर्वक सुना।

चीनी : साथी एस.पी. तिवारी, महासचिव टी.यू.सी.सी. के साथ साथी हंसराज अकेला, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टी.सी.सी.सी. राज्य इकाई, साथी रमेश चन्द्र शर्मा, साथी राजेन्द्र सिंह और अन्य साथियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में लेबर कमिश्नर श्री सिताराम शर्मा जी से कानपुर में 13 अगस्त 2009 को भेंट की और चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, बीड़ी मजदूरों आदि की समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की।

साथी राजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष राज्य चीनी उद्योग मजदूर फेडरेशन ने चीनी मिलों के निजीकरण, मजदूरों को पीआईबी का भुगतान न होना, आदि मुद्दों को श्री मीणा जी के सामने रखा, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे इस मामले को चीनी उद्योग के सीएमडी में इन मामलों को रखेंगे।

पश्चिम बंगाल में खाद्य आन्दोलन की 50वीं वर्षगांठ

31 अगस्त को विशाल रैली आयोजित करने की तैयारी

पश्चिम बंगाल में खाद्य आन्दोलन की 50वीं वर्षगांठ पर 31 अगस्त 2009 को एक विशाल आन्दोलन की तैयारी तेजी से की जा रही है। वाम दलों की ओर से एक विशाल रैली का आयोजन मेट्रो चैनल, कोलकाता में किया जायेगा। आपको ज्ञात होगा कि खाद्य आन्दोलन का आयोजन 'मूल्य वृद्धि के संदर्भ में' 31 अगस्त 1959 को वामदलों ने संयुक्त रूप से किया गया था तथा उस समय कि कांग्रेस सरकार ने बर्बर पुलिस फायरिंग करवाकर था जिसमें 80 लोग मारे गये थे और सैकड़ों लोग घायल हुये थे। फारवर्ड ब्लॉक के नेता साथी हेमन्ता बसु उस कमिटी के सचिव थे। के. एम.पी.पी, सीपीआई, बोलशेविक पार्टी, आरएसपी, एससीयूआई ने भी इसमें भाग लिया था।

31 अगस्त 2009 के वामदलों के संयुक्त कार्यक्रम के अलावा, फारवर्ड ब्लॉक की बंगाल राज्य कमिटी ने इसके लिये विशेष पहल कर रही है और इस संदर्भ में 50 हजार पोस्टर, 1959 के आन्दोलन से संबंधित फलेक्स, बैनरों आदि पर आन्दोलन के चित्रण आदि प्रदर्शित करेगी। छात्रों की ओर से एक पुस्तिका भी वितरित की जायेगी। इसके अलावा सभाओं का आयोजन विभिन्न जिलों में करेगी ताकि कोलकाता में 31 अगस्त 2009 को पार्टी की ओर से 50 हजार जनता को एकजुट किया जा सके।

केरल में दो दिवसीय पार्टी स्कूल आयोजित

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केरल राज्य कमिटी का दो दिवसीय पार्टी स्कूल का आयोजन 25 और 26 जुलाई 2009 को संगीता एकेडमी हॉल, थ्रिसुर में संपन्न हुआ।

पार्टी स्कूल की अध्यक्षता साथी वी. राम मोहन, महासचिव, केरल राज्य कमिटी, ने किया। इसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास ने किया। साथी बिश्वास ने कहा कि नई चुनौतियों का सामना करने के लिये पार्टी कैडरों और कार्यकर्ताओं के लिये पार्टी स्कूल की बहुत आवश्यकता है।

इसके अलावा जनसभा का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष साथी एन. वेलप्पन नायर ने किया। इस अवसर पर साथी के. आर. ब्रह्मानंदन, साथी जी. देवराजन, साथी थंकचन वर्गीस, साथ्ीा वेल्लादुरई पाण्डियन, साथी अरूण एस. सासी, साथी दिपीन थेक्कापुरम आदि ने भी वक्तव्य दिये।

नि:शुल्क परीक्षा व्यवस्था लागू की जाये, रोजगार को मूल संविधान में शामिल किया जाये

ऑल इण्डिया यूथ लीग की केन्द्रीय कमिटी की बैठक 25 अगस्त 2009 को नई दिल्ली के केन्द्रीय कार्यालय में संपन्न हुयी। बैठक की अध्यक्षता यूथ लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का. मोईनुद्दिन शम्स ने की।

प्रारम्भ में यूथ लीग केन्द्रीय कमिटी ने उन सभी संघर्षशील साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित किये जिन्होंने अपने प्राणों की आहूति देकर जनहित में वामपंथी आंदोलन के उसूलों को आगे बढ़ाया।

बैठक में यूथ लीग के राष्ट्रीय महासचिव साथी संजय भट्टाचार्य ने वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश किया, जिस पर चर्चा में केन्द्रीय कमिटी के अन्य सदस्यों का. अनिर्बन चौधुरी, का. अजय अग्निहोत्री, का. धमेन्द्र कुमार, का. रेहान अहमद खान, का. फरीद मोल्ला और का. रामकुमार दास ने भाग लिया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि 28 सितम्बर शहीद-ए-आजम भगत सिंह के जन्मदिवस को साम्राज्यवाद विरोधी दिवस के रूप में मनायेंगे।

बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी 21 अक्तूबर 2009 को 'युवा संघर्ष दिवस' के रूप में मनाया जायेगा। जिसमें संविधान में रोजगार दिये जाने को मूल अधिकार में शामिल किये जाने, राष्ट्रीय युवानीति, राष्ट्रीय खेल नीति घोषित करने, सरकारी नौकरियों में भर्ती पद्धति में

नि:शुल्क परीक्षा व्यवस्था लागू करने (जिसमें पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट जैसे आदि लिये जाने वाले शुल्क माफ किये जाने), नरेगा में 100 दिनों के स्थान पर 200 दिन किये जाने, न्युनतम मजदूरी 160 रुपये किये जाने, ग्रामीण के साथ-साथ शहरी युवाओं को भी शामिल किये जाने, नरेगा में पारदर्शिता लाये जाने, नरेगा में जन प्रतिनिधि कमिटी का गठन किये जाने, राज्य योजना को भी नरेगा में शामिल किये जाने जैसे मांगों को लेकिर राज्य मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री या माननीय राज्यपाल को ज्ञापन सौपा जायेगा।

21 अक्तूबर हिन्दुस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख है जिस दिन 1943 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सिंगापुर में अस्थायी आजाद हिन्द सरकार का गठन किये थे। इसी दिन के स्मरणार्थ यूथ लीग इस वर्ष 'युवा संघर्ष दिवस' के रूप में मनाने का निश्चय किया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि रेलवे से जुड़ी समस्याओं को लेकर, रेल की जमीन को निजी हाथों में पट्टे पर दिये जाने के खिलाफ रेलमंत्री को यूथ लीग के प्रतिनिधि ज्ञापन सौपेंगे। इसी प्रकार नौजवानों को रोजगार की मांग के साथ ही अल्पसंख्यकों तथा आदिवासियों की उन्नति की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौपा जायेगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि 31 अक्तूबर 2009 तक सदस्यता फार्म शुल्क सहित यूथ लीग के महामंत्री के पास जमा करा दी जाये।

इसके अलावा झारखण्ड इकाई के नवनिर्वाचित यूथलीग के महामंत्री का. हंजला बिन हक को तथा दिल्ली के साथी रामकुमार दास को सर्वसम्मति से केन्द्रीय कमिटी में शामिल किया गया। यूथ लीग दिल्ली इकाई के प्रभारी रहे का. अरूण चटर्जी के स्थान पर का. संजय भट्टाचार्य को प्रभारी की जिम्मेदारी सौपी गयी है।

बैठक में यूथ लीग के केन्द्रीय कार्यालय की आवश्यकता पर गम्भीरता से चर्चा की गयी तथा इसके लिये यूथ लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी मोइनुद्दीन शम्स को पार्टी के सम्मानित महामंत्री तथा पार्टी के सम्मानित यूथ लीग के प्रभारी से मिलकर उन्हें केन्द्रीय कार्यालय की आवश्यकता पर पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है यूथ लीग की सचिव मण्डल की बैठक नवम्बर 2009, कोलकाता में आयोजित की जायेगी।

सभी साथियों से निवेदन है कि उपरोक्त कार्यक्रमों को सुचारू रूप से सफल बनाने के लिये सभी राज्यों के प्रभारी अपने-अपने राज्य क्षेत्र में दिशा निर्देशित करें और इसके अधिक से अधिक प्रचार की व्यवस्था करें जिससे उपरोक्त कार्यक्रम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यादगार बनें।

पश्चिम बंगाल में जूट की खेती और उद्योग गहरे संकट में

हाल के समय में, पश्चिम बंगाल में जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल है। लेकिन हाल ही में टैक्सटाइल मंत्रालय ने जूट का समर्थन मूल्य कम करने की घोषणा की है, जिससे पश्चिम बंगाल के जूट कृषकों के लिये एक गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। मंत्रालय ने हाल ही में वी5 ग्रेड के लिये 1350/- रुपये से 1388/- रुपये, और टीडी5 ग्रेड के लिये 1400 से 1438 रुपये राज्य के विभिन्न जिलो में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा किया है किया है। इस घोषणा का प्रभाव यह हुआ है कि जूट की कीमत 1300 रुपये 1400 रुपये प्रति क्विंटल तक नीचे आ गया।

जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिये पश्चिम बंगाल राज्य इकाई की अग्रगामी किसान सभा ने राज्य के कई जिलों में जैसे कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शीदाबाद, नदिया और उत्तर 24 परगना जन आन्दोलन आरम्भ कर दिया है।

राजनीतिक हलको में यह आकलन है कि जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को करने के पीछे देश के प्लास्टिक लॉबी का हाथ है। इस प्रकार हमारी जूट की खेती और उद्योग के खिलाफ पूर्ण रूप से एक साजिश की जा रही है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल के दो महत्वपूर्ण केन्द्रीय मंत्री है, लकिन वे राज्य के जूट उत्पादकों की बढती कठिनाई में किसी भी प्रकार की रूचि नहीं ले रहे हैं।

अंडमान एवं निकोबार में सम्मेलन की कार्यकारीणी गठित

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की अंडमान और निकोबार इकाई की विस्तारित बैठक पोर्ट ब्लेयर में 12 अगस्त 2009 को आयोजित की गयी। साथी एम. लिंगामाया ने बैठक की अध्यक्षता की। केन्द्रीय कमिटी की ओर से पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री साथी नरेन दे और राष्ट्रीय सचिव साथी जी. देवराजन भी उपस्थित थे। साथी शिहाबुद्दीन ने संगनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत किया।

साथी नरेन दे ने व्याख्या करते हुये अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक की आवश्यकता को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने पार्टी के सदस्यों और पार्टी से सहानुभूति रखने वालों से आग्रह किया कि वे एकजुट होकर केन्द्र सरकार पर दबाव बनायें की इन द्वीपों का नाम बदल कर शहीद एवं स्वराज द्वीप कर दिया जाये जैसा की नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने 1944 में कहा था।

साथी जी. देवराजन ने अपना वक्तव्य रखते हुये कहा कि संप्रग सरकार की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ एक विशाल जन आन्दोलन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों और जन-विरोधी नीतियों के कारण ही आवश्यक वस्तुओं की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही

है। सरकार इसे काबू करने में विफल रही है। सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना चाहिये। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप की जनता से जन-आन्दोलन करने का आग्रह किया।

सभा में एकमत रूप से सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा हुयी। पोर्ट ब्लेयर और उत्तरी-मध्य जिला की सदस्यता को मान्यता देते हुये कार्यकर्ता सम्मेलन की तिथी तय की गयी। उत्तरी मध्य जिला का सम्मेलन 20 नवम्बर को बिल्ली ग्राउण्ड में होगा और पोर्ट ब्लेयर का जिला सम्मेलन 21 नवम्बर 2009 को डेलानीपुर कम्युनिटी हॉल में होगा। राज्य स्तरीय सम्मेलन 22 नवम्बर 2009 को पोर्ट ब्लेयर में किया जायेगा।

इसके अलावा तिरंगा पार्क में एक जनसभा का आयोजन किया गया और सम्मेलन की तैयारी के लिये कार्यकारिणी कमिटी का गठन किया गया और सभा में यह निर्णय लिया गया कि सम्मेलन की तैयारी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जायेगा।

सरकार की मुँह जुबानी हमदर्दी से जनता भ्रमित नहीं होने वाली

'खा गया दाल, पी गया तेल, ये देखो मनमोहना का खेल, रोजी-रोटी जो दे न सके, वह सरकार निकम्मी है' 'जनता भूखों मरती है, व्यवस्था मौज उड़ाती है'। पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करों - घोषित करों, ''भूखी जनता करे पुकार, बन्द करो महँगाई की मार''। इत्यादि नारों के साथ 2 अगस्त 2009 को अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की लखनऊ, उत्तर प्रदेश इकाई ने विधानसभा के सामने बढ़ती महँगाई और पूरे प्रदेश को सरकार द्वारा सूखाग्रेस्त न करने के विरोध में प्रदर्शन कर धरना दिया।

प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुये अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के प्रान्तीय अध्यक्ष साथी रामकिशोर एडवोकेट ने कहा कि सरकार को जमाखोरों, मिलावखोरों, मुनाफाखोरों को तुरन्त गिरफ्तार करना चाहिय। सरकार को चाहिये की खाद्यान्न वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाये और दोषी अधिकारियों को दण्डित करें। ऑल इण्डिया यूथ लीग के उत्तर प्रदेश प्रान्तीय संयोजक साथी अभिमन्यु सिंह ने कहा कि यह दु:ख की बात है कि देश का भविष्य, भारत का युवा वर्ग, महँगाई की मार से तड़प रहा है और उसे दो वक्त भरपेट भोजन भी नहीं पा रहा है। युवजन इस व्यवस्था से बुरी तरह आक्रोशित है। सरकारों को चाहिये की वह तुरन्त महँगाई पर रोक लगायें और प्रदेश सरकार पूरे देश को सूखाग्रस्त घोषित करें तथा जनता को उचित सहायता प्रदान करें। अब सरकार की मुँह जुबानी हमदर्दी से जनता भ्रमित होने वाली नहीं है।

धरने में अन्य लोगों के अतिरिक्त सुश्री अरूणा त्रिवेदी, सुश्री पूनम सिंह, एडवोकेट, सुश्री मधु श्रीवास्तव, फारवर्ड ब्लॉक के जिला अध्यक्ष साथी एन. सी. घोष एडवोकेट, जिला मंत्री साथी आर.के. सिंह, प्रान्तीय मंत्री साथी विरेन्द्र कुमार एडवोकेट, साथी बालकराम, साथी मुसाफिर लखनवी, साथी राधेश्याम, यूथ लीग के जिला संयोजक साथी रवी उपाध्यक्ष आदि प्रमुख थे।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के महासम्मेलन की तैयारी जोरों पर

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय सचिव मण्डल की बैठक 17 अगस्त 2009 को कोलकाता में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष साथी एन. वेलप्पन नायर ने की।

बैठक में कोलकाता होने वाली 17 से 21 दिसम्बर तक पार्टी की 16वीं महासम्मेलन की तैयारी पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी।

बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद सचिव मण्डल ने मामूली संशोधन के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसौदा पारित किया गया। दस्तावेजों का अंतिम मसौदा सभी राज्य इकाईयों को 31 अगस्त 2009 तक भेज दिया जायेगा तथा मसौदा पर शाखा, स्थानीय और राज्य स्तरीय पर चर्चा सितम्बर 2009 तक या उससे पहले विस्तार पूर्वक चर्चा हो सके।

सचिव मण्डल ने विभिन्न राज्यों के सम्मेलनों के लिये निम्नलिखित तिथियों की घोषणा की है:

हरियाणा	31, अक्तूबर 2009
पंजाब	1 नवम्बर 2009
झारखण्ड	7, 8 नवम्बर 2009
कर्नाटक	11, 12 नवम्बर 2009
केरल	13,14,15 नवम्बर 2009
तमिलनाडु	15,16,17 नवम्बर 2009
पाण्डीचेरी	18 नवम्बर 2009
मध्य प्रदेश	20, 21 नवम्बर 2009
राजस्थान	22 नवम्बर 2009
अण्डमान और निकोबार	22 नवम्बर 2009
त्रिपुरा	28, 29 नवम्बर 2009

मणिपुर	30 नवम्बर 2009
नागालैण्ड	1 दिसम्बर 2009
आसाम	2, 3 दिसम्बर 2009
उत्तर प्रदेश	2, 3 दिसम्बर 2009
बिहार	7, 8 दिसम्बर 2009
पश्चिम बंगाल	12, 13, 14, 15 दिसम्बर 2009

जम्मु में फारवर्ड ब्लॉक की कार्यकर्ता सम्मेलन।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की जम्मु के विजयपुर में 30 जुलाई 2009 को एक कार्यकारिणी सभा का आयोजन किया गया। जम्मु, कटुआ, साम्बा और राजौरी क्षत्र से कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। सभा में क्षेत्र की पार्टी सदस्यता की भी चर्चा की गयी।

साथी राजेन पादरी, अध्यक्ष अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक राज्य कमिटी ने सभा की अध्यक्षता की। साथी जी. देवराजन ने एकत्रित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने मुख्य रूप से केन्द्रीय कमिटी में लिये गये निर्णयों के अनुसार महँगाई के खिलाफ आन्दोलन करने और 16वीं महासम्मेलन की तैयारियों से अवगत कराया।

सभा में 15 सितम्बर 2009 को श्रीनगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। 15 सितम्बर 2009 को विभिन्न जिला इकाईयों की सम्मेलन और राज्य सम्मेलन के स्थान और तिथियों का निर्णय लिया जायेगा। उस सभा में पार्टी के केन्द्रीय नेता भी उपस्थित रहेंगे।

झारखण्ड राज्य कमिटी ने सम्मेलन में पार्टी सदस्यता प्रदान किया।

धनबाद में 15 अगस्त 2009 को एक आद्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। जहाँ झारखण्ड राज्य के सक्रिय और सहयोगी सदस्यता कार्ड प्रदान किया गया। जबकि सदस्यता कार्ड सौंपते हुये अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के महामंत्री साथी देवब्रत बिश्वास ने सदस्यों साथियों से कहा कि वे सभी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सपनों का एक समाजवादी भारत बनाने के लिये कार्य करते रहे।

साथी जनार्दन पाण्डेय, महासचिव झारखण्ड राज्य कमिटी ने भी दीक्षांत समारोह को सम्बोधित किया।